मंगलवार, 09 जून, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

फ्रेंच ओपन जीतकर इतिहास रचने वाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

जुबिन नौटियाल का 37 वा जन्मदिन

Page-05

राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामला राज्य की सबसे चर्चित भर्ती घोटालों में से एक है, जिसकी जांच एसओजी द्वारा की जा रही है। जांच में सामने आया है कि अभ्यर्थियों को मोटी रकम लेकर परीक्षा से पहले ही हल प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए गए थे। मामले में अब तक 146 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और पेपर लीक नेटवर्क की परतें लगातार खुल रही हैं।

राजस्थान SI भर्ती पेपर लीक मामला

मास्टरमाइंड के भाई की गिरफ्तारी

राजस्थान उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने पेपर लीक नेटवर्क के कथित सरगना हर्षवर्धन कुमार मीणा के भाई पुष्पेंद्र कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है। एसओजी की जांच में खुलासा हुआ है कि पुष्पेंद्र ने परीक्षा से पहले एक अभ्यर्थी को लीक हुआ और हल किया गया प्रश्नपत्र पढ़ाया था।अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल के अनुसार, मामले की जांच के दौरान पता चला कि हर्षवर्धन मीणा ने स्वरूपचंद मीणा से उसके पुत्र बृजेश कुमार मीणा को पेपर उपलब्ध कराने के बदले 45 लाख रुपये का सौदा किया था। जांच में सामने आया कि लीक हुआ सॉल्व्ड पेपर बृजेश को हर्षवर्धन के भाई पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने पढ़ाया था, जिससे वह परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके।एसओजी के मुताबिक, बृजेश कुमार मीणा को लिखित परीक्षा में हिंदी विषय में 200 में से 116.23 अंक और सामान्य ज्ञान में 200 में से 126.01 अंक प्राप्त हुए थे। इन अंकों के आधार पर वह लिखित परीक्षा में सफल भी हो गया था। हालांकि, बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में असफल होने के कारण उसका अंतिम चयन नहीं हो सका।जांच में यह भी सामने आया कि बृजेश कुमार मीणा ने 15 सितंबर 2021 को अजमेर केंद्र पर एसआई भर्ती परीक्षा दी थी। उसे 11 जून 2026 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि पुष्पेंद्र कुमार मीणा को 14 जून को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उसे 18 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है ताकि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा सके।एसओजी के अनुसार, पुष्पेंद्र कुमार मीणा पहले दौसा जिले में फायरमैन चालक के पद पर कार्यरत रह चुका है। उसके खिलाफ पूर्व में भी राजस्थान REET/RO भर्ती परीक्षा-2022 से जुड़े एक मामले में आरोप दर्ज हैं। उस पर जन्मतिथि में हेराफेरी कर अपनी जगह डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाने का आरोप है, जिसकी जांच अजमेर के सिविल लाइंस थाने में चल रही है।एसओजी ने बताया कि एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में अब तक 146 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसी पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में वैदिक मंत्र अनिवार्य

छत्तीसगढ़ सरकार के एक नए आदेश को लेकर राज्य की राजनीति में विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन वैदिक मंत्रों, गायत्री मंत्र और सरस्वती वंदना के पाठ को अनिवार्य कर दिया है। 16 जून 2026 से लागू हुए इस फैसले ने राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। जहां विपक्षी कांग्रेस इसे शिक्षा के भगवाकरण की दिशा में कदम बता रही है, वहीं भाजपा सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना का विकास करना है।स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में एक निर्धारित दैनिक दिनचर्या अपनाई जाएगी। इसके तहत सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र और महान विभूतियों के जीवन प्रसंगों का वाचन किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को मध्याह्न भोजन से पहले भोजन मंत्र का पाठ करना होगा। स्कूल दिवस का समापन राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र के साथ किया जाएगा।सरकार का दावा है कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास को बढ़ावा देना है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि इन प्रार्थनाओं और मंत्रों के माध्यम से छात्रों में अनुशासन, संस्कार और सकारात्मक जीवन मूल्यों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का किसी राजनीतिक या धार्मिक एजेंडे से कोई संबंध नहीं है।हालांकि कांग्रेस ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों को धार्मिक शिक्षा केंद्रों की तरह संचालित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में विभिन्न धर्मों और समुदायों के छात्र पढ़ते हैं, इसलिए किसी विशेष धार्मिक परंपरा से जुड़े मंत्रों का अनिवार्य पाठ संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के विपरीत है।

टीएमसी विधायक कुणाल घोष पर फेंका गया अंडा

पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता और विधायक कुणाल घोष पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर अंडा फेंके जाने की घटना सामने आई। यह घटना उस समय हुई जब कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकल रहे थे।घटना के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाला और संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बाद में चंदन नामक एक स्थानीय युवक ने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी।युवक ने दावा किया कि उसने जानबूझकर विरोध स्वरूप यह कदम उठाया है। पत्रकारों से बातचीत में उसने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं के व्यवहार और कार्यशैली से वह लंबे समय से नाराज था। उसने कहा कि उसके अनुसार जनता के साथ अन्याय हुआ है और इसी कारण उसने अपना विरोध दर्ज कराया।हालांकि, टीएमसी की ओर से इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। पार्टी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए राजनीतिक विरोध के नाम पर इस तरह की हरकतों की निंदा की है। वहीं, सुरक्षा एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि घटना के पीछे केवल व्यक्तिगत विरोध था या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी मौजूद है।

रेवंत रेड्डी बोले- पहले मोदी दें इस्तीफा, फिर मैं और मेरी कैबिनेट छोड़ेंगे पद

तेलंगाना की राजनीति में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। राज्य विधानसभा भंग कर नए जनादेश की मांग को लेकर शुरू हुए विवाद ने अब केंद्र और राज्य सरकारों की वैधता पर बहस का रूप ले लिया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी की चुनौती का जवाब देते हुए कहा कि वह अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद छोड़कर केंद्र सरकार भंग करनी होगी।रेड्डी ने कहा कि राजनीतिक चुनौतियां एकतरफा नहीं हो सकतीं और सभी दलों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और उसे सत्ता में बने रहने के लिए किसी अन्य दल के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता के जनादेश के आधार पर काम कर रही है, जबकि केंद्र की बीजेपी नीत सरकार कई सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर है।मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास पूर्ण और स्पष्ट जनादेश नहीं है, इसलिए उसे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देकर केंद्र सरकार को भंग करते हैं, तो वह भी अपनी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देने में कोई संकोच नहीं करेंगे।यह विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी सांसद एम. रघुनंदन राव ने कांग्रेस सरकार पर जनता की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को विधानसभा भंग कर दोबारा जनता के बीच जाने की चुनौती दी। राव ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री को अपनी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा है, तो उन्हें तत्काल इस्तीफा देकर नए चुनाव कराने चाहिए।बीजेपी सांसद ने यह भी दावा किया कि पार्टी के सभी आठ सांसद अपने पदों से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। दोनों दल अब जनादेश, बहुमत और राजनीतिक नैतिकता के मुद्दों पर आमने-सामने नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद तेलंगाना की राजनीति में और अधिक गर्माहट ला सकता है।

बिहार मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

राजस्थान उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने पेपर लीक नेटवर्क के कथित सरगना हर्षवर्धन कुमार मीणा के भाई पुष्पेंद्र कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है। एसओजी की जांच में खुलासा हुआ है कि पुष्पेंद्र ने परीक्षा से पहले एक अभ्यर्थी को लीक हुआ और हल किया गया प्रश्नपत्र पढ़ाया था।अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल के अनुसार, मामले की जांच के दौरान पता चला कि हर्षवर्धन मीणा ने स्वरूपचंद मीणा से उसके पुत्र बृजेश कुमार मीणा को पेपर उपलब्ध कराने के बदले 45 लाख रुपये का सौदा किया था। जांच में सामने आया कि लीक हुआ सॉल्व्ड पेपर बृजेश को हर्षवर्धन के भाई पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने पढ़ाया था, जिससे वह परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके।एसओजी के मुताबिक, बृजेश कुमार मीणा को लिखित परीक्षा में हिंदी विषय में 200 में से 116.23 अंक और सामान्य ज्ञान में 200 में से 126.01 अंक प्राप्त हुए थे। इन अंकों के आधार पर वह लिखित परीक्षा में सफल भी हो गया था। हालांकि, बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में असफल होने के कारण उसका अंतिम चयन नहीं हो सका।जांच में यह भी सामने आया कि बृजेश कुमार मीणा ने 15 सितंबर 2021 को अजमेर केंद्र पर एसआई भर्ती परीक्षा दी थी। उसे 11 जून 2026 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि पुष्पेंद्र कुमार मीणा को 14 जून को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उसे 18 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है ताकि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा सके।

फर्जीवाड़ा रोकने को सख्त सत्यापन व्यवस्था लागू: डीके शिवकुमार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की गारंटी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी और उनका लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू की जा रही है।सोमवार को गारंटी योजनाओं की समीक्षा के दौरान शिवकुमार ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है, लेकिन सरकार जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है जिन्हें पिछली सरकारें प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सकीं।हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ मामलों में योजनाओं का गलत इस्तेमाल सामने आया है। इनमें गलत तस्वीरें अपलोड करना, फर्जी मोबाइल नंबरों का उपयोग करना और लाभ राशि को गलत बैंक खातों में भेजना शामिल है। शिवकुमार ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रत्येक योजना का लाभ सीधे सही और पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की गारंटी योजनाएं केवल कर्नाटक के निवासियों और मतदाताओं के लिए हैं। दूसरे राज्यों के लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। मुफ्त बस यात्रा योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसका लाभ भी केवल कर्नाटक की पात्र महिलाओं और निवासियों तक सीमित रहेगा, ताकि सरकारी धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार ही हो सके।शिवकुमार ने बताया कि लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन को आसान बनाने के लिए एक नई प्रमाणीकरण प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके तहत कार्ड आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे बस यात्रा सहित अन्य योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी।

जी-7 शिखर सम्मेलन पर दुनिया की नजर

यूक्रेन युद्ध, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होगी निर्णायक चर्चा

दुनिया भर में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चुनौतियों के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ताजा रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका सहित परमाणु शक्तियों के शस्त्रागार की स्थिति का आकलन किया गया है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

फ्रांस के एवियां-ले-बैंस शहर में शुरू हुए जी-7 शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे समय में जब दुनिया एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही है, प्रमुख विकसित देशों के नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीकी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच पर एकत्र हुए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के राष्ट्राध्यक्षों की इस बैठक को आने वाले वर्षों की वैश्विक दिशा तय करने वाला सम्मेलन माना जा रहा है।इस वर्ष सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रूस-यूक्रेन युद्ध बना हुआ है। युद्ध के तीन वर्ष पूरे होने के बाद भी समाधान के स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से आर्थिक और सैन्य सहायता की मांग कर रहा है, जबकि यूरोप के कई देशों पर युद्ध का आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। सम्मेलन में इस बात पर चर्चा हो रही है कि यूक्रेन को किस प्रकार समर्थन जारी रखा जाए और साथ ही शांति वार्ता की संभावनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए।पश्चिम एशिया की स्थिति भी नेताओं की चिंता का प्रमुख विषय है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की दिशा में हुई प्रगति ने कुछ राहत अवश्य दी है, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता अभी भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं मानी जा रही। तेल आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सम्मेलन के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हैं। जी-7 देशों का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखना विश्व अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है।इसके अतिरिक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के तेजी से बढ़ते प्रभाव पर भी विशेष चर्चा हो रही है। विकसित देशों के नेता ऐसी नीतियां बनाने पर विचार कर रहे हैं जिनसे तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन मिले, लेकिन साथ ही डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके। कई विशेषज्ञों का मानना है कि एआई आने वाले दशक में दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को गहराई से प्रभावित करेगा।सम्मेलन में विकासशील देशों की चिंताओं पर भी चर्चा की जा रही है। बढ़ते कर्ज, महंगाई और व्यापारिक असंतुलन जैसी समस्याओं से जूझ रहे देशों के लिए नई आर्थिक साझेदारी और निवेश के अवसरों पर विचार किया जा रहा है। भारत सहित कई देशों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिससे वैश्विक दक्षिण की आवाज को भी मंच मिल रहा है।विश्लेषकों का मानना है कि सम्मेलन से निकलने वाले निर्णय केवल जी-7 देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनका प्रभाव पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ेगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्थिक असंतुलन पर बढ़ी वैश्विक चिंता

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सामने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का तेजी से विस्तार एक नई चुनौती बनकर उभरा है। तकनीकी विकास के साथ-साथ इसके सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी प्रभावों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी एआई के नियमन और उसके जिम्मेदार उपयोग को लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।विशेषज्ञों का मानना है कि एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, परिवहन और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसके माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने और सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि इसके साथ कई जोखिम भी जुड़े हुए हैं। रोजगार पर प्रभाव, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और गलत सूचना के प्रसार जैसी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं।कई देशों ने यह आशंका व्यक्त की है कि यदि एआई के लिए वैश्विक स्तर पर समान नियम नहीं बनाए गए तो तकनीकी प्रतिस्पर्धा असंतुलित हो सकती है। विकसित देशों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए एक साझा अंतरराष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जाना चाहिए, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिले और संभावित खतरों को भी नियंत्रित किया जा सके।सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। बढ़ता सार्वजनिक ऋण, व्यापारिक तनाव, महंगाई और विकासशील देशों की वित्तीय चुनौतियों पर नेताओं ने चिंता व्यक्त की। कई विशेषज्ञों का कहना है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक अंतर लगातार बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।

TMC के बागी सांसदों के एक नई पार्टी में शामिल होने के बाद राज्य में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में इस समय राजनीतिक माहौल बेहद गरम बना हुआ है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों के एक साथ नई पार्टी में शामिल होने के बाद राज्य में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इसी बीच हावडा स्थित नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के दफ्तर के बाहर सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए है। माना जा रहा है कि प्रशासन ने किसी भी संभावित विरोध, प्रदर्शन या तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। सोमवार सुबह से ही कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। सोमवार सुबह से ही कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। पार्टी दफ्तार के साथ-साथ आसपास के इलाके में भी पुलिस और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गईं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। सूत्रों के अनुसार, TMC के भीतर बढ़ते असंतोष और सांसदों के बड़े समूह के दल बदलने के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। स्थानीय स्तर पर पार्टी समर्थकों के बीच तनाव की आशंका को देखते हुए दफ्तर के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। बता दें कि हाल ही TMC के कम से कम 20 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर खुद के नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय की जानकारी दी है। यह पार्टी वर्ष 2022 में बनी थी और अब तक देश में उसका कोई सांसद नहीं था। बागी सांसदों ने लिखित पत्र देकर कहा कि वे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ काम करेंगे। सांसद काकोली घोष दस्तिदार ने बैठक के बाद कहा कि 20 सांसद अब आधिकारिक तौर पर NCPI का हिस्सा हैं।

रूस के भीषण हमले से कीव दहला, ऐतिहासिक मठ परिसर में लगी आग

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई प्रमुख शहरों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में कई नागरिकों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हमलों के कारण आवासीय इमारतों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है।यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि रूस ने एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग किया, जिनमें से कई को मार गिराया गया, लेकिन कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। राजधानी कीव में कई स्थानों पर विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं और आपातकालीन सेवाओं को तत्काल राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया गया। कई इलाकों में अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई।यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि रूस लगातार नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। उन्होंने पश्चिमी देशों से अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणाली और सैन्य सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है। उनका कहना है कि युद्ध के इस चरण में यूक्रेन को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। दूसरी ओर रूस ने दावा किया है कि उसके हमले केवल सैन्य ठिकानों और रणनीतिक लक्ष्यों पर केंद्रित थे। रूस का कहना है कि यूक्रेन भी उसके कई सीमावर्ती क्षेत्रों पर ड्रोन हमले कर रहा है, जिसके जवाब में कार्रवाई की जा रही है।लगातार बढ़ते हमलों के कारण शांति वार्ता की संभावनाएं कमजोर होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान तलाशने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध जितना लंबा चलेगा, उसका असर यूरोप के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता रहेगा।

तेल बाजार में आई राहत

अमेरिका-ईरान युद्धविराम समझौते से पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कई महीनों से जारी तनाव और सैन्य संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम को लेकर बनी सहमति ने पश्चिम एशिया में शांति की नई उम्मीद जगाई है। दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ताओं और क्षेत्रीय मध्यस्थों के प्रयासों के बाद संघर्ष को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस घटनाक्रम को हाल के वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है।संघर्ष के दौरान पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। तेल उत्पादन और समुद्री व्यापार प्रभावित होने की आशंका के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ गई थी। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बनी अनिश्चितता ने ऊर्जा आयातक देशों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है।युद्धविराम की खबर सामने आते ही वैश्विक बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समझौता स्थायी रूप लेता है तो इससे महंगाई के दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।हालांकि दोनों देशों के बीच कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक प्रतिबंधों जैसे विषयों पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहा है।संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे पश्चिम एशिया में लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता को कम करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार यदि दोनों पक्ष कूटनीतिक संवाद जारी रखते हैं तो क्षेत्र में स्थायी शांति की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।

संपादक की कलम से

महंगाई और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच संतुलन की चुनौती:

भारत इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आर्थिक विकास की संभावनाएं और वैश्विक चुनौतियां एक साथ मौजूद हैं। एक ओर देश दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताएं सरकार और नीति निर्माताओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता और मानसून को लेकर आशंकाएं ऐसे कारक हैं जो आने वाले महीनों में देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं इस बात का संकेत हैं कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझ रही है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए महंगाई केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब खाद्य पदार्थों, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सबसे अधिक असर निम्न और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी केवल आर्थिक आंकड़ों को बेहतर बनाए रखने तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि आम नागरिक के जीवन को भी सहज बनाए रखना आवश्यक हो जाता है।देश की कृषि व्यवस्था अब भी मानसून पर काफी हद तक निर्भर है। यदि वर्षा सामान्य से कम रहती है तो खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिसका सीधा असर बाजार कीमतों पर दिखाई देगा। सरकार को अभी से भंडारण, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि किसी भी संभावित संकट से समय रहते निपटा जा सके। साथ ही किसानों को तकनीकी सहायता, सिंचाई सुविधाएं और पर्याप्त समर्थन मूल्य उपलब्ध कराना भी जरूरी है।दूसरी ओर, वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है। देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल की कीमतों में वृद्धि केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवहन, उद्योग और कृषि क्षेत्र के माध्यम से पूरे अर्थतंत्र को प्रभावित करती है। इसलिए ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।विपक्ष द्वारा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाना लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि इन विषयों पर केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से समाधान नहीं निकलेगा। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और विपक्ष दोनों राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर रचनात्मक संवाद करें। संसद का आगामी सत्र इस दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है।भारत ने अतीत में कई आर्थिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। आज भी देश के पास मजबूत संस्थागत ढांचा, विशाल घरेलू बाजार और युवा जनसंख्या जैसी बड़ी ताकतें मौजूद हैं। आवश्यकता केवल दूरदर्शी नीति, प्रभावी क्रियान्वयन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की है। यदि सरकार समय रहते आवश्यक कदम उठाती है और सभी हितधारकों को साथ लेकर चलती है, तो वर्तमान चुनौतियां भी देश की प्रगति को रोक नहीं पाएंगी। बल्कि यही चुनौतियां भारत को अधिक आत्मनिर्भर, मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का अवसर भी बन सकती हैं।

महंगाई, तेल कीमतों और मानसून की चुनौती के बीच सरकार सतर्क,वित्त मंत्री ने जताई चिंता

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों का असर पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता ऐसे कारक हैं जो आने वाले महीनों में आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों की अस्थिरता तथा मानसून की स्थिति भारत की आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इन सभी पहलुओं पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है।वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों का असर पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता ऐसे कारक हैं जो आने वाले महीनों में आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करते हैं, उनके लिए तेल कीमतों में वृद्धि चिंता का विषय बन सकती है।उन्होंने बताया कि सरकार खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भी तैयारियां कर रही है। यदि मानसून सामान्य से कमजोर रहता है तो कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे खाद्यान्न और सब्जियों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना पर काम किया जा रहा है।राजनीतिक दृष्टि से वित्त मंत्री का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि संसद का मानसून सत्र निकट है और विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी तथा किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगातार दावा कर रहे हैं कि आम जनता बढ़ती कीमतों से परेशान है और सरकार को राहत के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाने चाहिए।हालांकि सरकार का कहना है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक सुधारों, डिजिटल भुगतान, आधारभूत ढांचे के विकास और निवेश आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां अधिक खराब नहीं होती हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी विकास दर बनाए रखने में सफल रहेगी।विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ सप्ताह आर्थिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण होंगे। मानसून की प्रगति, अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की स्थिति और संसद में होने वाली बहसें सरकार की आर्थिक रणनीति को नई दिशा दे सकती हैं।

भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

ओमान के निकट एक तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद देश की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार को अधिक सक्रिय और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश जानना चाहता है कि इस घटना पर सरकार का आधिकारिक दृष्टिकोण क्या है।कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विदेशों में रहने और काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और घटना की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।विपक्ष का आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर सरकार अक्सर अपनी उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रस्तुत करती है, लेकिन जब भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का सवाल आता है तो अपेक्षित सक्रियता दिखाई नहीं देती। कांग्रेस ने मांग की है कि विदेश मंत्रालय संसद में इस मामले पर विस्तृत बयान दे और यह स्पष्ट करे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।उधर सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है और संबंधित देशों के साथ आवश्यक संपर्क बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने मृतकों के परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद के आगामी मानसून सत्र में यह मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा जैसे विषयों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

महाराष्ट्र में फिर गरमाई सियासत, उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाकर दिखाई ताकत

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कुछ सांसदों के दल बदलने की अटकलों के बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने सभी लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाकर शक्ति प्रदर्शन किया। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने दावा किया कि संगठन पूरी तरह एकजुट है और किसी भी सांसद के पार्टी छोड़ने की संभावना नहीं है।पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़े कुछ नेता विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कथित 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चाएं भी सामने आईं। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक अफवाहें हैं जिनका उद्देश्य कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर करना है।बैठक में सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की। पार्टी नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में विपक्ष को कमजोर दिखाने के लिए जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) पूरी मजबूती के साथ जनता के मुद्दे उठा रही है और पार्टी में किसी प्रकार की टूट नहीं है।दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं का कहना है कि विपक्ष अपनी आंतरिक समस्याओं को छिपाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है, इसलिए यहां होने वाली हर राजनीतिक गतिविधि पर देशभर की नजर रहती है।आगामी महीनों में संसद सत्र, स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां और विभिन्न राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति को और अधिक रोचक बना सकते हैं। ऐसे में सभी दल अपने संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

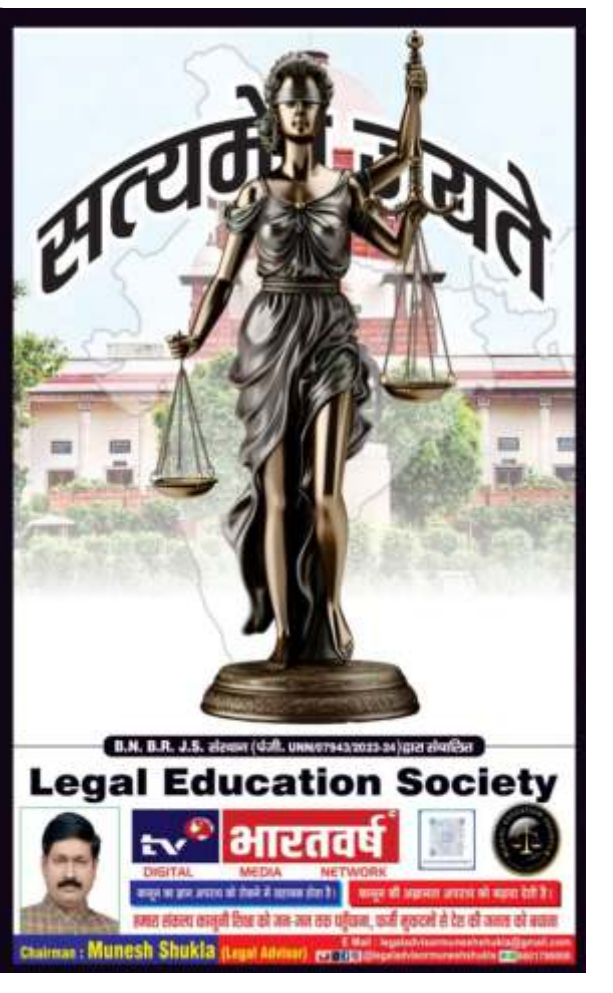

पीएचडी और शोध को बढ़ावा देने के लिए फेलोशिप योजनाओं का विस्तार,हजारों शोधार्थियों को मिलेगा लाभ

देश में उच्च शिक्षा और शोध को नई गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों ने शोधार्थियों के लिए फेलोशिप और वित्तीय सहायता योजनाओं के विस्तार पर जोर दिया है। शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हजारों पीएचडी शोधार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को शोध कार्य की ओर आकर्षित करना और भारत को ज्ञान एवं नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत बनाना है।वर्तमान समय में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ), प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (पीएमआरएफ) और विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों की विशेष योजनाओं के तहत शोधार्थियों को प्रतिमाह 37 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान कार्यों के लिए अलग से अनुदान, प्रयोगशाला सुविधाएं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध प्रस्तुत करने के अवसर भी दिए जा रहे हैं।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण

कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को अधिक महत्व दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि भारतीय विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान न रहकर वैश्विक स्तर के शोध केंद्रों के रूप में विकसित हों। इसी दिशा में उद्योग और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल फेलोशिप राशि बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। शोध के लिए बेहतर प्रयोगशालाएं, आधुनिक उपकरण, गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। कई विश्वविद्यालयों में अब भी संसाधनों की कमी शोध की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ऐसे में सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी ढांचे के विकास पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।छात्र संगठनों ने फेलोशिप योजनाओं के विस्तार का स्वागत किया है, लेकिन समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि कई बार शोधार्थियों को महीनों तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है, जिससे आर्थिक कठिनाइयां पैदा होती हैं।विशेषज्ञों के अनुसार यदि शोध और नवाचार को इसी प्रकार प्रोत्साहन मिलता रहा तो आने वाले वर्षों में भारत विज्ञान, तकनीक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर और मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है। इससे न केवल नई खोजों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

विश्वविद्यालयों में बहुविषयक शिक्षा को मिल रहा बढ़ावा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में तेजी से काम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल पर बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास और शोध आधारित अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ रोजगारोन्मुख और व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराना है।नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को विषय चयन में अधिक स्वतंत्रता देने पर जोर दिया गया है। अब विद्यार्थी विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसी पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर विभिन्न विषयों का संयोजन चुन सकते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्रों की रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि होगी तथा वे बदलती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकेंगे।देश के कई विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, बहु-प्रवेश और बहु-निकास व्यवस्था तथा अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया जा चुका है। इन सुधारों का उद्देश्य छात्रों को अधिक लचीलापन प्रदान करना और उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना है। साथ ही डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।हालांकि कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि नई नीति के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राज्यों, विश्वविद्यालयों और शिक्षकों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है तो आने वाले वर्षों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शोध क्षमता और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है।

सिर्फ 2 विकेट लेते ही बन जाएंगी दुनिया की नंबर-1 ऑल फॉर्मेट गेंदबाज

फ्रेंच ओपन जीतकर इतिहास रचने वाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव

जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है। रोलां गैरो में खेले गए फाइनल मुकाबले में उन्होंने इटली के फ्लावियो कोबोली को पांच सेटों तक चले रोमांचक मुकाबले में हराकर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया।29 वर्षीय ज्वेरेव लंबे समय से विश्व टेनिस के शीर्ष खिलाड़ियों में गिने जाते रहे हैं, लेकिन ग्रैंड स्लैम खिताब उनसे दूर रहा था। इससे पहले वह तीन बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में हार चुके थे। ऐसे में इस जीत को उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने दबाव के क्षणों में शानदार संयम दिखाया और निर्णायक सेट में पूरी तरह हावी होकर जीत दर्ज की।यह जीत इसलिए भी विशेष है क्योंकि ज्वेरेव लगभग तीन दशक बाद किसी जर्मन पुरुष खिलाड़ी के रूप में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। उनकी सफलता ने जर्मन टेनिस को नई पहचान दी है और देशभर में उनके प्रदर्शन की सराहना की जा रही है। जर्मनी के खेल जगत से जुड़े कई दिग्गज खिलाड़ियों और पूर्व चैंपियनों ने उन्हें बधाई देते हुए इस उपलब्धि को ऐतिहासिक करार दिया है।टूर्नामेंट के दौरान ज्वेरेव ने लगातार उच्च स्तर का खेल दिखाया। उन्होंने पूरे अभियान में केवल कुछ ही सेट गंवाए और कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखा। विशेषज्ञों का मानना है कि

इस खिताब के बाद उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा तथा वे आने वाले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में भी खिताब के प्रबल दावेदार बनकर उतरेंगे।मैच के बाद भावुक दिखाई दिए ज्वेरेव ने कहा कि इस ट्रॉफी के लिए उन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की है और कई बार निराशा का सामना भी किया। उन्होंने अपनी टीम, परिवार और प्रशंसकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके समर्थन के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। टेनिस विशेषज्ञों का मानना है कि यह जीत उनके करियर में एक नए युग की शुरुआत साबित हो सकती है और आने वाले वर्षों में वे विश्व टेनिस के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं।

पाकिस्तान को 64 रन से हराकर भेजा मजबूत संदेश

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 64 रन से करारी शिकस्त दी। एजबेस्टन मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट की अन्य टीमों को भी मजबूत संदेश दिया है। स्मृति मंधाना की आक्रामक बल्लेबाजी और दीप्ति शर्मा की घातक गेंदबाजी भारत की जीत के प्रमुख आधार बने।टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत साधारण रही, लेकिन इसके बाद स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पारी को संभाल लिया। मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें कई आकर्षक चौके और छक्के शामिल रहे। हरमनप्रीत ने भी महत्वपूर्ण योगदान देते हुए मध्यक्रम को मजबूती प्रदान की। अंतिम ओवरों में ऋचा घोष ने तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 170 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।171 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत में सकारात्मक बल्लेबाजी की और पावरप्ले में अच्छी रन गति बनाए रखी। एक समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला रोमांचक हो सकता है, लेकिन भारतीय स्पिन आक्रमण ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। दीप्ति शर्मा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से पाकिस्तान की बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने मात्र 10 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जो महिला टी20 विश्व कप इतिहास के सबसे यादगार प्रदर्शनों में गिना जा रहा है। उनकी गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए।दीप्ति शर्मा की इस उपलब्धि के साथ उन्होंने महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाजों में अपना स्थान और मजबूत कर लिया है। भारतीय टीम की युवा स्पिनर श्री चरणी ने भी महत्वपूर्ण विकेट लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा। परिणामस्वरूप पाकिस्तान की पूरी टीम 106 रन पर सिमट गई।

डायमंड लीग में भारतीय एथलेटिक्स की उम्मीदें बढ़ीं

भारतीय एथलेटिक्स के स्वर्णिम सितारे नीरज चोपड़ा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की उम्मीदों का केंद्र बने हुए हैं। हाल के महीनों में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले नीरज अब डायमंड लीग के आगामी चरण की तैयारी में जुटे हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी वर्तमान फॉर्म को देखते हुए वे इस सीजन में भी कई बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं।पेरिस ओलंपिक के बाद से नीरज ने अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय निरंतरता दिखाई है। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 85 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंककर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को उम्मीद है कि आगामी प्रतियोगिताओं में भी वे पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाएंगे।नीरज की सफलता का प्रभाव भारतीय एथलेटिक्स पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देशभर में युवा खिलाड़ी अब ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कई राज्यों में

एथलेटिक्स अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक खिलाड़ी की सफलता पूरे खेल तंत्र को प्रेरित कर सकती है और नीरज ने यही काम किया है।डायमंड लीग के आगामी चरण में नीरज को दुनिया के कई शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ियों से चुनौती मिलेगी। हालांकि उनके अनुभव और वर्तमान लय को देखते हुए भारतीय प्रशंसकों को उनसे एक और यादगार प्रदर्शन की उम्मीद है। कोचिंग स्टाफ का कहना है कि उनका पूरा ध्यान तकनीक और फिटनेस पर है ताकि बड़े टूर्नामेंटों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जा सके।भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें अब नीरज के अगले मुकाबले पर टिकी हैं। यदि वे इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखते हैं तो आने वाले वर्षों में भारतीय एथलेटिक्स को वैश्विक स्तर पर और अधिक पहचान मिलने की संभावना है।

मनोरंजन

मुख्य समाचार

नेटफ्लिक्स की बड़ी घोषणा: सनी देओल और अक्षय खन्ना की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'इक्का' 10 जुलाई 2026 को सीधे ओटीटी पर होगी रिलीज

मुंबई, 15 जून। मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) ने शनिवार को अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'इक्का' की आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। यह फिल्म 10 जुलाई, 2026 को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। यह एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें न्याय व्यवस्था, नैतिक संघर्ष और व्यक्तिगत सिद्धांतों की टकराहट को दिखाया गया है।

- फिल्म में सनी देओल और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म सनी देओल का ओटीटी पर डेब्यू है।
- लगभग तीन दशक बाद दोनों कलाकार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इससे पहले दोनों 1997 की सुपरहिट युद्ध फिल्म 'बॉर्डर' में साथ दिखाई दिए थे।
- फिल्म में सनी देओल एक प्रसिद्ध वकील की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें अपने अतीत से जुड़े एक व्यक्ति (अक्षय खन्ना) का बचाव करने की मजबूरी होती हैं। मामला उनके सिद्धांतों और परिवार दोनों को कठिन परीक्षा में डाल देता है।
- तिल्लोतमा शोम लोक अभियोजक की भूमिका में हैं, जबकि दीया मिर्जा सनी देओल की पत्नी के किरदार में नजर आएंगी।
- निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपने दमदार स्टारकास्ट, कसी हुई कहानी और भावनात्मक टकराव के कारण चर्चा में है।

अन्य समाचार

पुणे में फिल्म प्रमोशन इवेंट के दौरान बेकाबू भीड़, शाहिद कपूर-कृति सेनन और रश्मिका मंदाना को सुरक्षित निकाला गया

पुणे, 15 जून। फीनिक्स मॉल, विमाननगर में कल शाम उस समय हड़कंप मच गया जब फिल्म 'कॉकटेल 2' के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में पहुंचे शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की एक झलक पाने के लिए फैंस की भारी भीड़ बेकाबू हो गई।

- जैसे ही सितारे स्टेज पर पहुंचे, हजारों की संख्या में मौजूद फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच गया।
- भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़कर स्टेज की ओर दौड़ लगा दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई।
- धक्का-मुक्की के कारण सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और कलाकारों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा।
- पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और सितारों को भारी सुरक्षा के बीच वहां से सुरक्षित निकाला गया।
- इस घटना ने एक बार फिर बड़े सार्बजनिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अन्य समाचार

जुबिन नौटियाल का 37वां जन्मदिन, संघर्ष से सफलता तक का प्रेरणादायक सफर

मुंबई, 15 जून। मशहूर प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल आज 14 जून को अपना 37बां जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी मीठी और दिल को छू लेने वाली आवाज़ से उन्होंने लाखों दिलों में खास जगह बनाई हैं।

- जन्म: 14 जून 1989 को देहरादून (उत्तराखंड) में।
- पिता रामशरण नौटियाल एक बिजनेसमैन और राजनीतिजा हैं, माता नीना नौटियाल गुहिणी हैं।
- शुरुआत: रियलिटी शो 'इंडियन आइंडल' से की, लेकिन शुरुआती दौर में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा।
- ब्रेकथ्रू: साल 2014 में फिल्म 'सोनाली केबल' के गाने 'एक मुलाकात' से मिली पहचान।
- हिट गाने: 'मेहरबानी', 'जिंदगी' (बजरंगी भाईजान), 'तू इतनी खूबसूरत हैं', 'बंदिया', 'समंदर', 'मेरे घर राम आए हैं', 'नारायण मिल जाएगा' आदि।
- आज जुबिन नौटियाल अपने टेलेंट, मेहनत और लगन के दम पर बॉलीवुड़ के टॉप सिंगर्स में शुमार हैं।

जेवर एयरपोर्ट से उड़ी विकास की पहली उड़ान,

172 किसान पहुंचे लखनऊ

जेवर एयरपोर्ट की पहली उड़ान से 172 किसान लखनऊ पहुंचे। भूमि देने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। यह एयरपोर्ट क्षेत्रीय विकास, रोजगार, निवेश और वैश्विक पहचान का नया प्रतीक बनकर उभरा है

उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) ने सोमवार को एक नया इतिहास रच दिया। जेवर एयरपोर्ट से पहली वाणिज्यिक उड़ान सुबह 10:30 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इस विशेष उड़ान में 172 किसान सवार थे, जिन्होंने एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी भूमि दी थी। यात्रियों में 20 महिला किसान भी शामिल थीं। लखनऊ पहुंचने पर सभी किसानों का स्वागत किया गया तथा बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव करने वाले किसानों के चेहरे पर उत्साह और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। महिला किसान रीता ने बताया कि उन्होंने पहली बार हवाई जहाज में सफर किया और यह अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय रहा। वहीं व्हीलचेयर पर यात्रा कर रहीं कमलेश ने कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी चार बीघा जमीन दी थी और आज उस परियोजना को साकार होते देख उन्हें बेहद खुशी हो रही है।इससे पहले सुबह 7:30 बजे लखनऊ से इंडिगो की पहली उड़ान जेवर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। इस ऐतिहासिक उड़ान में अभिनेत्री गुल पनाग भी शामिल रहीं। जेवर एयरपोर्ट पर विमान के पहुंचने के साथ ही प्रदेश के विमानन इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया।करीब 11 हजार करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। चार चरणों में विकसित होने वाला यह एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इसकी आधारशिला 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी और लगभग पांच वर्षों में इसका पहला चरण तैयार किया गया है। एयरपोर्ट की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यात्री प्रवेश के बाद 20 मिनट से भी कम समय में बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जेवर एयरपोर्ट दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। उन्होंने कहा कि एक समय यह इलाका अपराध और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह विकास, निवेश और वैश्विक पहचान का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कभी पिछड़ा माना जाने वाला यह क्षेत्र अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी जमीन और सहयोग के बिना इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करना संभव नहीं था। उन्होंने विश्वास जताया कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को आर्थिक प्रगति, निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा तथा प्रदेश को वैश्विक मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित करेगा।

रेलवे स्टेशनों पर बिजली बचाने के लिए डिजिटल पहल

रेलवे स्टेशनों पर बिजली की अनावश्यक खपत रोकने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने एक नया डिजिटल कदम उठाया है। मंडल ने 'आईआर नियंत्रक' नामक एक विशेष ऐप विकसित किया है, जिसकी मदद से स्टेशन परिसर में लगे बिजली उपकरणों की निगरानी और संचालन अब एक ही प्लेटफॉर्म से किया जा सकेगा। इस परियोजना के तहत लखनऊ जंक्शन सहित 18 स्टेशनों पर करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से यह प्रणाली स्थापित की जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर अब तक बिजली उपकरणों का रखरखाव और संचालन मैनुअल तरीके से किया जाता रहा है। इसके लिए फील्ड स्टाफ रजिस्टर में विवरण दर्ज करता है, लेकिन कई बार पंखे, लाइटें और एयर कंडीशनर जरूरत न होने पर भी चालू रह जाते हैं, जिससे बिजली की अनावश्यक खपत होती है। नई प्रणाली लागू होने के बाद रेलवे प्रशासन को एक क्लिक पर यह जानकारी मिल सकेगी कि कौन-सा उपकरण चालू है, बंद है या कहीं बिजली आपूर्ति बाधित तो नहीं हुई है। नई व्यवस्था में कंट्रोल रूम में मौजूद कर्मचारी ऐप के माध्यम से स्टेशन पर लगे बिजली उपकरणों को दूर से ही नियंत्रित कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर पंखे, लाइटें और एसी को चालू या बंद किया जा सकेगा। इससे न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि उपकरणों के संचालन में भी पारदर्शिता और दक्षता आएगी।

पटाखा फैक्ट्री में धमाका, एक युवती की मौत

लखनऊ में सोमवार को एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट इतना तेज था कि फैक्ट्री वाला मकान पूरी तरह ढह गया और ईंटें बिखर गईं। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर फायर ब्रिगेड, SDRF और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है। पटाखा फैक्ट्री के आसपास कोई दूसरा मकान नहीं था, लेकिन धमाके की आवाज सुनकर गांववाले मौके पर पहुंच गए। घटना नगराम थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार, यह विस्फोट ग्राम देवती निवासी मो. शफीक (26) की पटाखा फैक्ट्री में हुआ। फैक्ट्र का लाइसेंसधारी है और यह गांव के बाहर स्थित है। आसपास आबादी नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। हादसे में मारिया (22) और मोहित गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान मारिया की मौत हो गई। वह फैक्ट्री मालिक की भांजी थी। मोहित की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। मोहित गांव का रहने वाला है। घटना के समय वह जानवर चरा रहा था और फैक्ट्री के पास पानी पीने आया था। शुरुआती जांच में किसी अन्य के हताहत होने की जानकारी नहीं है। घटना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आसपास के लोगों के मुताबिक, हादसा करीब सुबह 11:30 बजे हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि उसकी आवाज करीब डेढ़ से दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह हादसा शाम के समय होता, जब लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है, तो बड़ा नुकसान हो सकता था। जनहानि कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली।

पीजीआई प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस

साजिशकर्ता आलमबाग से दबोचा गया

लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या के मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने सोमवार तड़के आलमबाग बस स्टेशन के पास से हत्या की साजिश में शामिल एक लाख रुपए के इनामी आरोपी गंगाराम यादव को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक, 27 मई 2026 को पीजीआई इलाके में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना पीजीआई में मुकदमा दर्ज कर एसटीएफ की विभिन्न टीमों को आरोपियों की तलाश में लगाया गया था। इससे पहले 31 मई को एसटीएफ मुख्य साजिशकर्ता समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। शूटरों समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी थी। एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली कि मामले में वांछित और एक लाख रुपए का इनामी आरोपी गंगाराम यादव आलमबाग बस अड्डे के पास मौजूद है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गंगाराम यादव ने बताया कि उसने दिनेश कुमार यादव और उसके चालक मुकर्रबीन उर्फ मुबीन के कहने पर हत्या के लिए शूटरों की व्यवस्था कराई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी हत्या की साजिश में अहम भूमिका निभाने वालों में शामिल है। गिरफ्तार आरोपी को पीजीआई थाने में दर्ज हत्या के मुकदमे में दाखिल कर दिया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। एसटीएफ अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

सफाई कर्मचारियों की मौतों पर

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सख्त

लखनऊ में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष की बैठक । हरदीप सिंह गिल ने सफाई कर्मचारियों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आर्थिक सशक्तिकरण और मुआवजा की राशि दिलाने समेत विभिन्न मुद्दों पर बैठक किया जिसमें मुख्य रूप से सफाई कर्मचारियों को सेफ्टी इक्विपमेंट ना मिलने और सफाई के दौरान हो रही मौतों पर नाराजगी जताई। हरदीप सिंह गिल ने बताया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद है। हाल ही में तीन मौत हुई है जिसको लेकर राष्ट्रीय सफाई आयोग आज बैठक कर रहा है। इसमें जिलाधिकारी नगर , निगम के अधिकारी और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। देखने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और मैनुअल स्कैवेंजिंग act 2011 का पालन नहीं हो रहा है। मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाई जा रही है सुरक्षा इक्विपमेंट नहीं दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से मौत हो रही है इस पर हमने जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किए हैं। साथ ही 15 दिनों के अंदर इन्हें मुआवजा देने के लिए कहा गया है।

जनगणना ड्यूटी से गायब 435 कर्मचारियों पर कार्रवाई

जनगणना-2027 के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ लखनऊ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 435 कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर निगम प्रशासन ने संबंधित थानों में तहरीर भेज दी है और पूरे मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भी उपलब्ध करा दी गई है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार जनगणना कार्य के लिए कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका था और उन्हें आवश्यक स्टेशनरी व अन्य सामग्री भी उपलब्ध करा दी गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी निर्धारित ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में इस प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के आठों जोनों में जनगणना कार्य के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। इनमें बेसिक शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सिंचाई विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, पंचायत विभाग तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय समेत कई विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। आरोप है कि इनमें से अनेक कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित रहे।नगर निगम द्वारा जोनवार अनुपस्थित कर्मचारियों की सूची संबंधित थानों को भेजी गई है। जोन-1 के 69 कर्मचारियों के खिलाफ थाना हजरतगंज में तहरीर दी गई है।

जोन-7 के 62 कर्मचारी नियुक्ति सामग्री और स्टेशनरी लेने तक नहीं पहुंचे, जिनके खिलाफ थाना गाजीपुर में शिकायत भेजी गई है। इसके अलावा जोन-3 के 244 कर्मचारियों के खिलाफ थाना अलीगंज, जोन-6 के 165 कर्मचारियों के खिलाफ थाना ठाकुरगंज तथा जोन-8 के 75 कर्मचारियों के खिलाफ थाना आशियाना में कार्रवाई की संस्तुति की गई है। जांच के दौरान कई कर्मचारियों के मोबाइल फोन बंद मिले, जबकि कुछ के संपर्क नंबर गलत पाए गए। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि जनगणना अधिनियम-1948 की धारा 4, 5 और 11 के तहत नियुक्त कर्मचारी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में जनगणना कार्य में सहयोग करना उनका कानूनी दायित्व है। नियमों के उल्लंघन पर एक हजार रुपये तक जुर्माना और तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में ड्यूटी पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

उन्नाव में अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का शुभारंभ,

सीडीओ कृति राज ने किया योग अपनाने का आह्वान

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जनपद उन्नाव में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ हुआ। शहर स्थित निराला उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) कृति राज के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, समाजसेवियों तथा आम नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। यह योग सप्ताह 15 जून से 21 जून तक मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जिले के विभिन्न स्थानों पर योग एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी कृति राज ने भगवान धन्वंतरि के पूजन एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास किया। योग प्रशिक्षकों ने योग के वैज्ञानिक महत्व और स्वास्थ्य लाभों की विस्तृत जानकारी भी दी।इस अवसर पर सीडीओ कृति राज ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन, मानसिक संतुलन और निरोगी समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाता है तथा जीवनशैली से जुड़ी अनेक बीमारियों से बचाने में सहायक सिद्ध होता है।उन्होंने जनपदवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित योग करना चाहिए। सीडीओ ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "Yoga for Healthy Ageing" निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवनशैली के लिए प्रेरित करना है।कृति राज ने जानकारी दी कि योग सप्ताह के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग शिविर, जनजागरूकता अभियान और सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि योग को जन-जन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों से सहभागिता करने का आह्वान किया।कार्यक्रम में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. राजकुमार, आयुष विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने स्वस्थ एवं निरोग जीवन के लिए नियमित योगाभ्यास करने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने बताया कि पूरे सप्ताह योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

फ्लिपकार्ट कर्मचारी वेतन वृद्धि के लिए प्रदर्शन पर

उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र स्थित फ्लिपकार्ट कंपनी में सोमवार को कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर सोहरामऊ पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारियों तथा कंपनी प्रबंधन के बीच संवाद स्थापित कराया। सोहरामऊ थाना प्रभारी अरविंद पांडेय ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। उन्होंने कहा कि फिलहाल क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनके वेतन में उचित बढ़ोतरी नहीं की गई है। उनका कहना है कि काम का दबाव बढ़ने के बावजूद उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और अन्य लाभ नहीं मिल रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कंपनी परिसर में धरना शुरू किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बताया कि वे अपनी समस्याओं को प्रबंधन के सामने लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक वेतन वृद्धि और अन्य मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस मामले में फ्लिपकार्ट प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कर्मचारियों की मांगों और प्रबंधन के रुख के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।

उन्नाव के पीपरखेड़ा गांव में जलभराव

उन्नाव जिले के सदर तहसील क्षेत्र के पीपरखेड़ा गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को जल निकासी और रास्ते की गंभीर समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पुराने पानी निकासी मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिससे कई घरों में पानी भर रहा है। उन्होंने प्रशासन से 8 फुट चौड़े रास्ते और नाली के निर्माण की मांग की है। ग्रामीण रज्जन पाल ने बताया कि गांव में वर्षों पुराना पानी निकलने का रास्ता था, जिससे आसपास के घरों और खेतों का पानी निकलता था। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास प्रधान द्वारा तालाब की ओर जाने वाले पानी के निकास को बंद करा दिया गया। इसके बाद खेतों और तालाब क्षेत्र में निर्माण कार्य होने से जल निकासी पूरी तरह प्रभावित हो गई। रास्ता बंद होने के कारण घरों के सामने पानी जमा होने लगा है। बारिश के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बच्चों के डूबने जैसी संभावित दुर्घटनाओं की आशंका व्यक्त की है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर पहले थाने में भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से समस्या के तत्काल समाधान की मांग की। ग्रामीण महिला सुताना ने बताया कि गांव में नाली और 8 फुट चौड़े खड़ंजे वाले रास्ते की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जगह-जगह बांध लगा दिए गए हैं, जिससे पानी निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। अब घरों के दरवाजों पर पानी भरने की स्थिति बन रही है। महिला ने जानकारी दी कि गांव में लगभग 50 घर इस समस्या से प्रभावित हैं। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि जल्द से जल्द पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाए और आवागमन के लिए स्थायी रास्ता उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत पत्र जमा कर दिया है। अधिकारियों की ओर से मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलने की बात कही गई है। अब ग्रामीणों को अपनी समस्या के समाधान का इंतजार है।

खाद्य विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप,

व्यापार मंडल ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन

उन्नाव में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने खाद्य प्रशासन विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। व्यापारी नेता अखिलेश अवस्थी ने बताया कि उन्होंने 2 जून को खाद्य प्रशासन विभाग में कथित भ्रष्टाचार और अधिकारियों के कार्य करने के तरीके को लेकर एक ज्ञापन दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस ज्ञापन के चार दिन बाद ही खाद्य अधिकारी प्रियंका सिंह की ओर से उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। अवस्थी के अनुसार, नोटिस में यह उल्लेख किया गया था कि वह स्वयं खाद्य व्यापारी हैं, इसलिए इस तरह की शिकायत या आवाज नहीं उठा सकते। व्यापारी नेता ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में यदि वह व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या वे जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उनकी समस्याएं नहीं उठा सकते? उन्होंने आरोप लगाया कि नोटिस के जरिए उन पर कार्रवाई की चेतावनी देकर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अवस्थी ने चिंता व्यक्त की कि यदि एक व्यापारी नेता के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो आम व्यापारी अपनी समस्याएं अधिकारियों तक कैसे पहुंचाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग एक वर्ष पहले भी भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर उनके और एक अन्य व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अखिलेश अवस्थी ने कहा कि अब फिर से उसी तरह कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है, जिसे व्यापारी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे व्यापारियों की समस्याओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते रहेंगे और किसी दबाव में पीछे नहीं हटेंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद व्यापारी नेताओं ने बताया कि अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि एडीएम ने पूरे प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। व्यापारी नेता ने बताया कि नोटिस का जवाब भी दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जानकारी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग को भी दे दी गई है।

ग्रेट निकोबार परियोजना के विरोध में हस्ताक्षर अभियान

उन्नाव जनपद के बीघापुर तहसील प्रांगण में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने एक हस्ताक्षर अभियान और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। यह अभियान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किया गया था। इसमें क्षेत्रीय नागरिकों और ग्रामीणों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कथित तौर पर एक बड़े कॉर्पोरेट घराने (अडानी समूह) को सौंपने के सरकारी फैसले का विरोध किया। अभियान का नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। उन्होंने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विकास के नाम पर देश की प्राकृतिक धरोहरों और जंगलों को निजी हाथों में सौंप रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'ग्रेट निकोबार' परियोजना के तहत लगभग 161 वर्ग किलोमीटर के अछूते जंगलों को नष्ट करने की योजना है, जो दिल्ली के कुल क्षेत्रफल से चार गुना बड़ा है। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस कदम से लगभग 1.5 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे और हजारों सालों से वहां रह रही प्राचीन जनजातियां बेघर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में इस परियोजना का विरोध करती है और जब तक सरकार यह फैसला वापस नहीं लेती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। तहसील परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी, उन्नाव (166 भगवंत नगर विधानसभा) के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बैनर-पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान "ग्रेट निकोबार को बचाना है, कॉर्पोरेट लूट को रोकना है" जैसे नारे लगाए गए। इसके बाद एक विशाल कैनवास पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों, किसानों और अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर राम किशोर पाल, राम चंद्र गुप्ता, रमेश सिंह, आकाश सिंह (एडवोकेट), अशोक पटेल (एडवोकेट), प्रदीप चन्देल, राजू सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने देश की प्राकृतिक संपदा को बचाने का संकल्प लिया।

भीषण गर्मी का असर, जिला अस्पताल की ओपीडी में उमड़ी मरीजों की भीड़

उन्नाव में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सोमवार को जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखी गई। गर्मी और उमस के कारण जिले में बीमारियों में वृद्धि हुई है। ओपीडी खुलते ही बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, जिससे इमरजेंसी वार्ड में भी दबाव बढ़ गया। सोमवार को जिला अस्पताल में 1,000 से अधिक मरीजों ने उपचार के लिए पंजीकरण कराया। इनमें जुकाम, बुखार, डायरिया, पेट दर्द और गर्मी से संबंधित बीमारियों के मरीज सर्वाधिक थे। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ओपीडी कक्षों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। मरीजों की भीड़ को देखते हुए चिकित्सकों ने अतिरिक्त समय देकर उपचार किया। डॉ. कौशलेंद्र, डॉ. अमित और डॉ. शोभित ने ओपीडी में मरीजों की जांच कर दवाएं दीं। चिकित्सकों ने मरीजों को गर्मी से बचाव के आवश्यक उपाय भी सुझाए। जिला अस्पताल में एक्स-रे और रक्त जांच कराने वाले मरीजों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई। जांच केंद्रों के बाहर भी मरीजों और उनके तीमारदारों की लंबी कतारें लगी रहीं। चिकित्सकों के अनुसार, लगातार बढ़ते तापमान में लापरवाही बरतने से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को गर्मी में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।

जेहटा–माल रोड पर सरकारी सीमेंट की कथित कालाबाजारी का मामला, जांच की उठी मांग

सूत्रों का कहना है कि यदि सरकारी निर्माण सामग्री के दुरुपयोग के आरोप सही साबित होते हैं तो इसका सीधा असर विकास परियोजनाओं पर पड़ सकता है। सरकारी योजनाओं के लिए निर्धारित सामग्री में कमी आने से निर्माण कार्य प्रभावित हो सकते हैं और परियोजनाओं की लागत भी बढ़ सकती है।

राजधानी लखनऊ के माल थाना क्षेत्र अंतर्गत जेहटा-माल रोड पर सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल होने वाली सीमेंट की कथित कालाबाजारी का मामला चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों और क्षेत्रीय सूत्रों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक निजी प्रतिष्ठान पर सरकारी कार्यों के लिए आवंटित सीमेंट की बिक्री की जा रही है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और लोग पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी विकास परियोजनाओं के लिए आने वाली निर्माण सामग्री को कथित रूप से निजी स्तर पर बेचा जा रहा है। आरोपों के केंद्र में जेहटा-माल रोड स्थित 'श्री श्याम ट्रेडर्स' नामक प्रतिष्ठान का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक संबंधित विभागों की ओर से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि जिन निर्माण सामग्रियों का उपयोग सड़कों, पुलियों, सरकारी भवनों और अन्य विकास कार्यों में होना चाहिए, वे कथित रूप से निजी गोदामों और दुकानों तक पहुंच रही हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ सीमेंट की बोरियों पर सरकारी उपयोग से संबंधित चिन्ह और निर्देश भी देखे गए हैं, जिसके बाद संदेह और गहरा गया है। लोगों का कहना है कि यदि सरकारी योजनाओं के लिए खरीदी गई सामग्री का उपयोग निर्धारित कार्यों के बजाय निजी लाभ के लिए किया जा रहा है, तो यह न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला है बल्कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। जेहटा-माल रोड पर जिस स्थान को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह क्षेत्र का व्यस्त मार्ग माना जाता है। पेट्रोल पंप के सामने स्थित होने के कारण यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में स्थानीय नागरिक यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि वास्तव में कोई अनियमितता हो रही है तो संबंधित विभागों और निगरानी एजेंसियों की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि सरकारी सामग्री की कथित बिक्री लंबे समय से जारी है, तो इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए थी। इस मामले ने प्रशासनिक निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था को लेकर भी बहस छेड़ दी है। पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कथित रूप से सरकारी सीमेंट निजी प्रतिष्ठान तक कैसे पहुंच रहा है। सरकारी परियोजनाओं में उपयोग होने वाली सामग्री की खरीद, भंडारण और वितरण की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। ऐसे में यदि किसी निजी दुकान तक ऐसी सामग्री पहुंचती है तो इसकी पूरी सप्लाई चेन की जांच आवश्यक हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मामले की जांच केवल दुकान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि सामग्री किस स्रोत से आई, उसके परिवहन में कौन शामिल था और क्या किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है। जांच एजेंसियों को रिकॉर्ड, परिवहन दस्तावेज और संबंधित विभागों के अभिलेखों का मिलान करना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

वाराणसी के लहरतारा स्थित बसों के स्टैंड को बंद कर दिया गया

वाराणसी से गाजीपुर का सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब मुसीबत थोड़ी बढ़ाने वाली है। वाराणसी के लहरतारा स्थित बसों के स्टैंड को बंद कर दिया गया है और प्रॉपर्टी के मालिक ने वहां वाहनों को खड़ा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद वाहन स्वामी नए स्टैंड की तलाश में जुट गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बौलिया से लहरतारा मार्ग पर लगने वाले भीषण जाम की समस्या को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है। दरअसल, बसों के संचालन से इस मार्ग पर घंटों जाम लगा रहता था। वाराणसी से गाजीपुर जाने वाले यात्रियों के लिए अब बस स्टैंड का पता बदलने वाला है। लहरतारा स्थित निजी प्रॉपर्टी पर संचालित हो रहे बस स्टैंड को बंद कर दिया गया है। यहां प्रॉपर्टी के मालिक ने गेट पर 'यहां वहां खड़ा करना प्रतिबंधित है' का बोर्ड लगा दिया है। इस बोर्ड के लगने के बाद बस संचालक नई जगह तलाशने में जुटे हुए हैं। इससे पहले यातायात पुलिस ने भी सड़क के किनारे खड़ी होने वाली बसों के खिलाफ जल्दी अभियान चलाने की घोषणा की थी। दरअसल, ट्रैफिक पुलिस को पिछले कई महीनों से लहतारा पर लगातार जाम लगने की समस्या की शिकायतें मिल रही थी। जाम लगने के कारण फुलवरिया के संपर्क मार्ग भी प्रभावित हो रहे थे। वहीं, सड़क पर निर्माण कार्य भी चल रहा है, इसके कारण भी अत्यधिक जाम लग रहा था और सड़क केवल 10 फीट ही रह गई थी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने या फैसला लिया कि बस स्टैंड को वहां से हटाया जाए। बौलिया से लहरतारा मार्ग पर निजी प्रॉपर्टी पर बस स्टैंड का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था। यह जाम का एक प्रमुख कारण था। वहीं, सड़क के निर्माण के बाद मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया गया था। इससे समस्या और बढ़ गई। आलम यह है कि अतिक्रमण के कारण 26 फीट की सड़क केवल 10 फीट तक सिमट कर रह गई थी, जिसके कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी और लोगों को 10 मिनट का सफर करने में आधे घंटे का समय लग जा रहा था।

योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट के कमर्शियल ऑपरेशन को, एक ऐतिहासिक क्षण बताया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर और देश के एविएशन सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया और इस प्रोजेक्ट की सफलता का श्रेय किसानों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन देने वाले किसानों की सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एयरपोर्ट उनके सहयोग और सरकार की समय पर काम पूरा करने की प्रतिबद्धता की वजह से ही बन पाया है। उन्होंने कहा कि जेवर, गौतम बुद्ध नगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश के एविएशन सेक्टर के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो गई हैं। प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर को याद करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी थी और अधिकारियों के लिए सख्त समय-सीमा तय की गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को 100 दिनों के भीतर ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की समय-सीमा दी थी। एक चुनौती थी, लेकिन किसानों ने हम पर भरोसा जताया। उन्होंने आगे कहा कि ज़मीन अधिग्रहण के दौरान शुरू में जो विरोध हुआ, उसे बातचीत से सुलझा लिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने लगभग 100 किसानों के साथ बैठकर उन्हें समझाया कि यह विकास का एक सुनहरा मौका है। आपकी ज़मीन एक नए भविष्य की नींव बनेगी। इलाके में आए बदलाव का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर, जो कभी अपराध और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा था, अब विकास के एक बड़े केंद्र के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से कार्गो सुविधाओं, एयरक्राफ्ट की देखरेख और ग्लोबल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विदेशी हब पर भारत की निर्भरता कम होगी। आदित्यनाथ ने आने वाले समय में बनने वाले संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ज़िक्र किया, जिसमें यमुना अथॉरिटी के तहत टाटा सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस, कई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिग्री कॉलेज, मेडिकल और स्पोर्ट्स सुविधाएं, ट्रॉमा सेंटर और ओलंपिक स्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक इनडोर स्टेडियम शामिल हैं।

पेट्रोल का रुपया मांगने पर दबंगों ने सेल्स मैन की पिटाई कर दी

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पेट्रोल का रुपया मांगने पर दबंगों ने सेल्स मैन की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं दबंगों ने अपने साथियों को बुलवाकर पेट्रोल पंप में जमकर तोड़फोड़ भी की। इस पूरी घटना में दबंगों के घर की महिलाएं भी शामिल रही। सेल्स मैन ने दबंगों पर चालीस हजार रुपए की नगदी छीन ले जाने का आरोप लगाया है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पाकर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का है। सदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अल्हनापुर का रहने वाला कोमल कुमार पर्वतपुर चौराहे पर बने ओम साईंनाथ पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के पद पर कार्यरत हैं। ओम साईंनाथ पेट्रोल पंप पर रविवार देर शाम नीरज अपने बहनोई के साथ पहुंचा और अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया। बताया जाता है कि जब सेल्स मैन कोमल ने पेट्रोल के रुपए मांगे तो नीरज ने रुपए ना देते हुए सेल्समेन कोमल से हाथापाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं नीरज ने इसकी जानकारी अपने घर वालों को दे दी, जिसके बाद नीरज के भाई और घर की महिलाएं हाथों में लाठी डंडा लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और सेल्समेन कोमल सहित अन्य कर्मचारियों को लाठी डंडों से मारने पीटने लगे। सेल्समेन कमल का आरोप है कि नीरज और उसके परिवार वालों ने पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की और कार्यालय पर भी पथराव किया। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में सेल्समैन कोमल ने खरीद ₹39 हजार की नगदी छीन ले जाने का भी आरोप लगाया है। मारपीट की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दबंगों ने पेट्रोल पंप पर किस तरह से मारपीट की। मारपीट की इस घटना में कई लोगों को चोटें आई हैं। वहीं, थानाध्यक्ष श्यामू कन्नौजिया ने बताया कि पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और घटना की सत्यता की जांच कर रही है।